



OKEDIA™
Pavitra

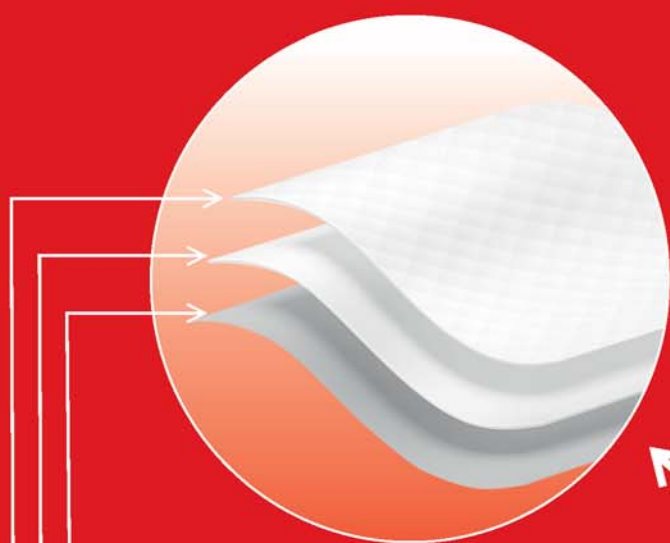
आपका आटा घर कैसे आता है?

पहली बार

आटा, सूजी, दलिया, बेसन में
ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन

3 LAYER PACKAGING

- STRONGEST BARRIER IN THE CATEGORY
- STAYS FRESH WITHOUT PRESERVATIVES
- HANDLES HUMIDITY & TRANSIT



(INNER) PE:
LOCKS IN FRESHNESS & AROMA

(MIDDLE) MET PET:
PREVENTS LIGHTS & AIR

(OUTER) MATT BOPP:
STRENGTH + PREMIUM FINISH



MUST TRY OUR:

शरबती सुपीरियर आटा । देशी चक्की आटा । सूजी । बेसन । गेहूँ

COMING SOON:

दाल । चावल । मसाले । कुकिंग ऑयल । ड्राई फ्रूट्स । चाय

ORDER
ON WEBSITE



ORDER
ON APP



ORDER ON CALL
1800 120 2727

ORDER
ON WHATSAPP



T&C Apply.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फॅक्स:- 0294-2410146

वर्ष: 32

संख्या: 319

प्रभात

उदयपुर, शनिवार 20 सितम्बर, 2025

आर.जे. 7202

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप के टैरिफ के ‘‘ श्राप ’’ को भारतीय ज्वैलर्स ने वरदान में तब्दील किया

ज्वैलरी पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ को, बड़ी होशियारी से कानूनी दाँव-पेच से 5.5 प्रतिशत टैरिफ में बदला

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19, सितंबर। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत से आभूषण आयात पर 5० प्रतिशत टैरिफ लगाया, तो इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के सबसे बड़े सोने और हीरे के आभूषणों के सप्लायरों में से एक को करारा झटका देना था। अमेरिका के आभूषण आयात में भारत का एक बड़ा हिस्सा है और इस शुल्क से कीमतें बढ़ने, मार्जिन कम होने और लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देने वाले उद्योग को झटका लगने का खतरा है। लेकिन इस समस्या को एक अनूठा ट्विस्ट देते हुए, भारतीय ज्वैलर्स ने टैरिफ की दीवार को पार करने का एक रास्ता खोज लिया है। इस काम में सबसे आगे हैं, मुंबई स्थित आभूषण निर्माता गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके पास लगभग चार दशकों का वैश्विक अनुभव है। टैरिफ से कुचले जाने के बजाय, कंपनी ने इसे एक अवसर में

बदल दिया है। इसका राज अमेरिकी टैरिफ कानून के एक अनदेखे प्रावधान में छिपा है: यदि कच्चा माल अमेरिका का है और प्रोसेसिंग के लिए विदेश भेजा जाता है और तैयार माल के रूप में वापस आता है, तो आयात शुल्क सिर्फ अतिरिक्त वैल्यू एडिशन पर ही लागू होता है। गोल्डियम ने अपनी सप्लाई चेन को इस ब्रूट के अनुसार दोबारा ढाल लिया है। यह व्यवस्था इस प्रकार काम करती है। कंपनी अमेरिका से सोना खरीदती है, जिससे उसे टैरिफ नियमों के तहत ‘‘घरेलू’’ दर्जा मिल जाता है। आधे-तैयार आभूषण भारत भेजे जाते हैं, जहाँ कारीगर इन आभूषणों को पॉलिश करते हैं और हीरे जड़ते हैं। इन

■ अमेरिका के टैरिफ कायदे-कानून के अनुसार, अगर किसी भी कच्चे माल की खरीद अमेरिका में होती है तथा इस खरीद को विदेश भेजकर ‘‘प्रोसेस’’ कराया जाता है तो वह तैयार माल जब अमेरिका में बिक्री के लिये आता है तो उस प्रॉडक्ट की ‘‘प्रोसेसिंग लागत’’ पर ही टैरिफ लगता है, जो लगभग 5.5 प्रतिशत ही होता है, पर, अगर सीधा तैयार माल अमेरिका भेजा जाए तो उस पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगता है।

■ भारतीय ज्वैलर्स अमेरिका में सोना खरीद कर, ‘‘सेमी फिनिशड’’ हालत में भारत भेज रहे हैं। भारतीय कारीगर उस ‘‘सेमी फिनिशड’’ सोने की ज्वैलरी को पॉलिश आदि करके चमकाकर, उसमें हीरे, माणिक, रूबी, आदि रत्न, डिजाइन के अनुसार सैट करके अमेरिका वापस भेज देते हैं, बिक्री के लिए। अतः अब निर्यात की गई ज्वैलरी पर केवल 5.5 प्रतिशत टैरिफ लगता है, न कि 50 प्रतिशत जो सीधे अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर लगता।

उन्नत उत्पादों को फिर से अमेरिका निर्यात किया जाता है। 5० प्रतिशत का कठोर टैरिफ चुकाने के बजाय,

गोल्डियम को अतिरिक्त श्रम और हीरों पर केवल 5.5 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है, जो प्रतिस्पर्धियों के

मुकाबले बहुत कम है।

गोल्डियम के लिए, यह सिरुं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभाध्यक्ष के ओ.एस.डी. दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने से इन्कार किया तथा हाई कोर्ट को इंगित किया कि वह राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें, ‘‘ट्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजीव दत्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट को उनके खिलाफ केस करने वाले वकीलों को डराने-धमकाने के आरोपों में एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों के अनुसार, आज सुबह स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आवास पर जाकर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने मेहता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, और यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजीव दत्ता के खिलाफ एफ आई आर दर्ज न हो। राजीव दत्ता की ओर से

■ विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, स्वयं ओम बिडला शुक्रवार की सुबह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर गए, उन्हें बताने कि दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वे (तुषार मेहता) दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने दें।

■ राजीव दत्ता की ओर से कई बड़े-बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उनके मामले की पैरवी करने के लिए। पर, फिर सुप्रीम कोर्ट राजीव दत्ता से काफी सख्ती से पेश आया और पूछा कि याचिका दायर करने वालों के खिलाफ पाँच-पाँच केस दर्ज करवाये गये हैं तथा उन्हें धमकी दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में देश के नामी वकीलों की टीम ने पैरवी की, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 5 झूठे केस क्यों दर्ज किए गए और उन्हें असामाजिक तत्वों के मार्फत क्यों धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दत्ता को

यह विकल्प जरूर दिया है कि वे चाहें तो दोबारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जयपुर में एफ आई आर लेकिन अब तक हाई कोर्ट द्वारा दर्ज करने का जो निर्देश पुलिस को दिया गया था, वह अभी तक लागू नहीं किया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंगर जुबिन गर्ग की हादसे में मौत

नई दिल्ली, 19 सितम्बर। बॉलीवुड के गलियारों से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। 9० के दशक में हिंदी सिनेमा को या अली, सुबह-सुबह, दिल तु ही बता और जिन्या रे जियारे जैसे कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर जुबिन गर्द का निधन हो गया है।

52 साल के असम के मशहूर सिंगर और कलचरल आइकन जुबिन गर्ग की जान स्कूबा डाइविंग करते हुए गई है।

■ जुबिन गर्ग सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे वहाँ हादसे में उनकी मौत हो गई। गर्ग असम के कलचरल आइकन थे।

उनके निधन की जानकारी असम के कैबिनेट मंत्री ने शुक्रवार की दोपहर में

शेयर की है। सिंगर जुबिन गर्ग जब स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो उस दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ। सिंगापुर पुलिस ने मौके पर जाकर उन्हें समुद्र से रेस्क्यू किया और तुरंत ही पास के अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पूरी मेडिकल केयर के बावजूद, उन्हें बचाया नहीं जा सका। जुबिन गर्ग सिंगापुर में गॉथ ईस्ट फेस्टिवल को अर्टेंड करने के लिए गए थे, जहां उन्हें 2० सितंबर को परफॉर्म करना था।

नयी दिल्ली, 19 सितंबर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डीयूसयू) चुनावों में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत हासिल की है। एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल कर एक बार फिर से इतिहास रचा है। जबकि एनएसयूआई को सिर्फ उपाध्यक्ष पद से ही

एसआई पेपर लीक में एक और प्रोबेशनर गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2०21 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, एक प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है, जो चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में तैनात था। गिरफ्तार प्रोबेशनर एसआई परीक्षा से पहले लीक सॉल्व पेपर को पढ़ कर चयनित हुआ था। एसओजी फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2०21 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, प्रोबेशनर एसआई कैलाश कुमार विश्‍नोई निवासी सांवर जिला जालोर गिरफ्तार किया गया है। कैलाश कुमार एसआई भर्ती पेपर की दोनों परियों की लिखित परीक्षा में लीक हुआ सॉल्वड पेपर पढ़ कर चयनित हुआ था और वर्तमान में पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में पुलिस एसआई (प्रोबेशनर) है। अब तक 56 एसआई सहित, कुल 127 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2०21 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से साल 2०24 में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

‘आईबी के आग्रह पर मैं आतंकियों से मिला, इसे अब मेरे खिलाफ ‘‘यूज़’’ किया जा रहा है’

तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी कश्मीरी नेता यासीन मलिक ने हाई कोर्ट में दायर 81 पेज के हलफनामे में दावा किया

- जाल खंभाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली,19 सितंबर। मृत्युदंड की सजा पाए कश्मीर के पूर्व अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दावा किया है कि 199० में गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार 6 सरकारों वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक-द्वारा कश्मीर मुद्दे पर बातचीत और समाधान के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया था।

मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि 2००6 में उन्होंने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी हाफिज सईद और अन्य उग्रवादियों से मुलाकात की थी, और यह मुलाकात तत्कालीन खुफिया ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर वी.के. जोशी के कहने पर हुई थी। उन्होंने कहा, मुझे विशेष रूप से हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी नेताओं से मिलने के लिए

■ मलिक ने कहा, 20०6 में आईबी के स्पेशल डायरैक्टर वी.के. जोशी के कहने पर मैं हाफिज सईद व अन्य आतंकियों से मिला था। मुलाकात के बाद मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन् से बात कर उन्हें जानकारी दी थी।

■ मलिक ने कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्र.मंत्री मनमोहन सिंह ने मुलाकात कर कहा था कि वे कश्मीर मुद्दे का हल करना चाहते हैं।

कहा गया था। यह तर्क दिया गया था कि आतंकवाद और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकती, खासकर जब राजधानी में बम धमाका हुआ था। मलिक ने आगे कहा कि इस मुलाकात के बाद जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन से मुलाकात की और उन्हें पूरी जानकारी

दी। मलिक, जिन्होंने तिहाड़ जेल नंबर 7 के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के सह-हस्ताक्षर के साथ 81 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकी नेताओं से मुलाकात के बाद जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साउदी अरब व पाकिस्तान का सुरक्षा अनुबंध क्या केवल आपसी सुरक्षा का वादा है?

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19, सितंबर। ‘‘स्वराज्य’’ पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुए रणनीतिक समझौते का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। विश्लेषण में कहा गया है कि इस समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी और पाकिस्तानी आधिकारिक मीडिया ने कहा है कि यह समझौता किसी भी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करता है और दशकों से चली आ रही रक्षा साझेदारी को संस्थागत रूप देता है। ऐतिहासिक रूप से, सऊदी-पाक सुरक्षा सहयोग काफी गहरा रहा है। सन् 1947 में पाकिस्तान को मान्यता देने

वाले शुरुआती देशों में सऊदी अरब भी था और 1951 की ‘‘ट्रूटी ऑफ फ्रेंडशिप’’ ने उनके करीबी रिश्तों की नींव रखी। 196० के दशक से, पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिक और प्रशिक्षक भेजे हैं और हजारों सऊदी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। रियाद इस रिश्ते के तहत अक्सर इस्लामाबाद को कर्ज और तेल-क्रेडिट के रूप में आर्थिक मदद भी देता रहा है। नया समझौता ऐसे समय आया है, जब क्षेत्र में अस्थिरता है। खाड़ी देशों में सीमापार संघर्षों और अमेरिका की कम होती दखलंदाजी के कारण सुरक्षा चिंता बढ़ी है। हाल के वर्षों में गाजा में

इज़राइल का युद्ध और पड़ोसी देशों पर उसके हमले, जिनमें 9 सितम्बर 2025 को दोहा पर हवाई हमला शामिल है, अरब देशों को राजधानियों को बेचैन कर चुके हैं। खाड़ी नेताओं को अब केवल अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करने में हिचक होने लगी है, क्योंकि वॉशिंगटन इज़रायल का खुला समर्थन करता है। इसी बीच, इस साल की शुरुआत में भारत ने एक संक्षिप्त संघर्ष के अनर्गत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान फिर से गहरी आर्थिक मुसीबत में पड़ चुकता था, जबकि उसने हाल ही में उससे थोड़ा

■ शीत युद्ध के प्रारंभिक दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका से ऐसे कई समझौते (पैक्ट्स) किये थे तथा अमेरिका ने कोई गारंटी नहीं दी थी कि पाकिस्तान पर कोई हमला होने पर, अमेरिका उसके पक्ष में युद्ध भूमि में कूद पड़ेगा।

■ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह साउदी अरब व पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का लक्ष्य भारत नहीं है, बल्कि इस उत्पत्ति का मुख्य कारण है, अमेरिका का आँख बंद करके इज़रायल का साथ देना, चाहे गाजा स्ट्रिप पर इज़रायल का हमला हो या 9 सितंबर 2025 को इज़रायल द्वारा बमबारी। अतः अब खाड़ी देश केवल अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते।

बाहर निकलना शुरू किया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सऊदी-पाकिस्तानी समझौता इन्हीं दबावों को प्रदर्शित करता है। भारतीय अधिकारियों

ने, इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि सरकार को पहले से पता था कि ऐसा समझौता हो सकता है और अब उसके

राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर का अध्ययन किया जाएगा। भारतीय मीडिया ने बताया कि बातचीत के दौरान सऊदी अधिकारियों ने भारत को भरोसे ले रखा

था, यानी दिल्ली पूरी तरह अंधेरे में नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषक इस समय को अमेरिका की पीछे हटने वाली भूमिका और मध्य पूर्व की उथल-पुथल से जोड़कर देखते हैं, न कि भारत के लिए किसी सीधी धमकी के रूप में। कुल मिलाकर, भारत अचानक चौंका नहीं और अधिकारियों ने सतर्क चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वे देखेंगे कि यह समझौता उपमहाद्वीप और क्षेत्र की स्थिरता पर कैसा असर डालता है। क्या इसमें कोई सुरक्षा गारंटी शामिल है? हाँ और नहीं। इस समझौते की मुख्य धारा कहती है कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा।

यह मूल रूप से परस्पर रक्षा की प्रतिबद्धता है। इस नज़रिए से यह एक तरह की सुरक्षा गारंटी तो देता है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ किसी हमले को रोकने या जवाब देने का वादा करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुख्यतः राजनीतिक और प्रतीकात्मक है। जारी किये गये बयानों में साझा रोकथाम और परामर्श पर जोर है, लेकिन इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि किसी हमले की स्थिति में सऊदी या पाकिस्तान बिना शर्त फ़ौज भर्जेंगे ही। पर्यवेक्षक इसकी तुलना ‘‘नाटो के आर्टिकल 5’’ से करते हैं, क्योंकि इसमें साझेदार को परस्पर समर्थन का वचन तो दिया गया है लेकिन वास्तविक सैन्य कार्रवाई का फ़ैसला हालात देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले के शीतयुद्ध कालीन अमेरिका के साथ रक्षा समझौते भी स्वतः (ऑटोमैटिक) हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते थे।

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने की आर.पी.ए. में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि यही बुनियादी प्रशिक्षण पुलिस के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें एक आदर्श अधिकारी बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आगामी समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शर्मा शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षान्त परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बैच के 76 प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, लगन और कड़ी तपस्या से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा की। इससे साइबर अपराध, आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपराध इत्यादि के सम्बन्ध में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आर.पी.एस. के 55वें बैच के दीक्षान्त समारोह में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।

बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी शामिल होना अत्यंत गर्व की बात है। महिला पुलिस अधिकारी से महिलाएं अपनी समस्याएं बेझिझक बताती हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं।

शर्मा ने कहा कि वर्तमान में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई-नई चुनौतियों से लड़ने के लिए पुलिस को

निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के साथ ही तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक की समझ भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए ईमानदारी सबसे शक्तिशाली हथियार है। पुलिस को किसी भी तरह के दबाव में ना आकर सदैव धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस के लिए टीम वर्क पर जोर देते हुए कहा कि पुलिसिंग एक टीम का काम है। जब हम साथियों के साथ

मिलकर काम करते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा और विश्वास से ही हम प्रत्येक चुनौती का आसानी से सामना कर सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक अपराधों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में

■ प्रशिक्षु आर.पी.एस. के 55वें बैच का दीक्षान्त समारोह आयोजित

■ अपराध के बदलते स्वरूप में पुलिस रहे सजग एवं अपडेट : भजनलाल शर्मा

18.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार के मामलों में भी 9.24 प्रतिशत की कमी आई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रख न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर तकनीकी नवाचार, त्वरित अनुसंधान एवं कार्यकुशलता का अग्रगण्य कदम है। शर्मा ने इस अवसर पर राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया तथा सामूहिक फोटो खिंचवाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीक्षान्त परेड का निरीक्षण किया तथा परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत तथा निदेशक आरपीए एस. सेंगाथर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देबाशीष पृष्ठि ने किया हाऊसिंग बोर्ड के शिविर का निरीक्षण

प्रमुख शासन सचिव ने शहरी सेवा शिविर में आमजन से लिया फीडबैक

जयपुर (कासं)। नगरीय विकास एवं

आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्ठि ने शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत्त-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिविर में आ रहे आमजन के लिए माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए साथ ही आमजन के साथ संवाद करते हुए फीडबैक भी लिया। शिविर में आए हुए कई लाभार्थियों ने व्यवस्थाओं की सराहा तथा समस्याओं के तत्काल निस्तारण पर राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। मण्डल अध्यक्ष द्वारा आर्वाटियों को त्वरित राहत प्रदान करने के विभिन्न कार्यों का एवं मण्डल द्वारा जारी किये जा रहे प्रपत्रों का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान पृष्ठि ने शिविर में लाभान्वित विभिन्न आर्वाटियों को अदेय प्रमाण पत्र, पंजीजन प्रपत्र इत्यादि वितरित किये गये।



आवासन एवं नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्ठि ने शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत्त-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की मण्डल द्वारा आयोजित शिविरों में अब तक कुल 316 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों का निस्तारण भी जल्द से जल्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शिविरों में आवासीय योजनाओं,

भवन निर्माण अनुमति, लीज कन्वर्जन, नामान्तरण, बकाया निस्तारण सहित अन्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सचिव गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता प्रथम अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव व पांच बिजली कंपनियों के एम.डी. और अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि बिजली कंपनियों के इंजीनियरों को यूडीएच में नियुक्ति क्यों दी गई है। जस्टिस एसपी शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश पब्लिक अरोस्ट करणन संस्था की जनहित याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की पांच बिजली कंपनियों ने जेईएन की भर्ती की थी। लेकिन बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच विभाग में भेज

■ मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों ने जे.ई.एन. की भर्ती की थी, परंतु बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच में भेज दिया गया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन हैं।

दिया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन हैं। केवल सरप्लस होने पर ही एक निगम से दूसरे निगम में नियुक्ति का नियम है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान,नियम या एक्ट नहीं है जिसमें किसी निगम या बोर्ड से सीधे ही सरकार में नियुक्ति दी जा सके। वहीं नगरीय विकास विभाग में इनकी नियुक्ति में

जिन नियमों का उल्लेख किया है उनके अनुसार इनको यूडीएच में समाहित नहीं कर सकते। ऐसे में ये नियुक्तियां पिछले दवाबों से दी हैं और इनमें नियमों का पालन नहीं किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा और राज्य सरकार से पूछा है कि इन अफसरों को किन नियमों से बिजली कंपनी से यूडीएच में समाहित किया गया है।

रिलायंस रिटेल मार्ट पर 100 किलो एक्सपायरी सामग्री जब्त

जयपुर । सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने प्रताप नगर स्थित मैसर्स रिलायंस रिटेल स्टोर से लगभग 100 किलो अवधिपार खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करवाई है। यह कार्रवाई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हुई।

पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे ग्रामीण तब दर्ज हुई भू-माफियाओं के खिलाफ एफ.आई.आर.

बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के आतंक और अवैध कब्जों की शिकायत लेकर पहुंचे थे लोग

जयपुर (कासं)। बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के बढ़ते आतंक और अवैध कब्जों से त्रस्त ग्रामीणों ने आखिरकार पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ से मुलाकात कर ज़ापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने एसीपी बस्सी को भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

प्रभावित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भूमाफिया गिरोह उनकी वैध रूप से खरीदी गई दुकानों और भूखंडों पर जबरन कब्जा कर रहा है। भू-माफियाओं ने बारंडूवाला तोड़कर व पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूखंडधारियों को जान से मारने की धमकियां दी।

पीडित सतीश सोनी ने बताया कि आरोपी उनकी दुकानें तोड़कर मलबा तक ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर ले गए ताकि दुकान का सबूत भी मिटाया जा सके। वहीं, रामदयाल जोगी ने कहा कि वे 20 वर्षों से अपने मकान में रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी है, इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गैरकानूनी कब्जे किए और दुकानों व भूखंडों को नुकसान पहुंचाया।

उल्लेखनीय है कि गोनेर रोड स्थित सिमरन वाटिका में वर्ष 2005 में भूमि विक्रय हुई थी। इसके बाद से लोगों ने मूल खातेदारों से भूखंड खरीदकर कॉलोनियों विकसित की और निर्माण कार्य किया।

पुत्र से जुड़े मामले में उडीसा के पूर्व डीजी विद्याभूषण मोहंती दोष मुक्त

जयपुर (कासं)। सेट्रल जेल जयपुर में सजायापात्र पुत्र को 18 साल पहले 20 नवम्बर, 2006 को फेरौल पर छुड़ाने के बाद फरार कराने तथा पकड़ने गई वैशाली नगर-जयपुर पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-04, मेट्रो-द्वितीय ने आरोपी रहे उडीसा के पूर्व महा निदेशक होमगार्ड 75 वर्षीय विद्याभूषण मोहंती को दोषमुक्त कर दिया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने लाल कोठी पुलिस थाने में 10 जनवरी, 2007 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। अनुसंधान पुलिस ने पूर्व आईपीएस विद्याभूषण मोहंती के खिलाफ अदालत ने 23 जनवरी, 2008 को चार्जशीट पेश की थी। विद्या भूषण मोहंती



बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं की शिकायत लेकर स्थानीय ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचे।

पीडितों का कहना है कि इस कॉलोनी में 20 से अधिक लोगों ने भूखंड और दुकानें खरीदी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई नहीं करती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें रामबाबू शर्मा, कमल कुमार शर्मा, मुकेश मोना और बाबूलाल मोना समेत कई लोगों पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और मारपीट कर डराने-धमकाने का आरोप है। पूर्व में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पीडित ने एसीपी विनय डी.एच. से भी शिकायत की

थी। इसके बाद एसीपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी चन्द्रमोहन मीना ने भी पीडितों से फोन पर बात कर हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश शर्मा ने बताया कि पीडितों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कोर्ट में पेश कर दावा किया जाएगा। उन्होंने भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को गलत ठहराते हुए पीडितों को हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

2 क्विंटल डोडा-चूरा तस्करी में लिप्त दंपति व बेटा गिरफ्तार

जयपुर । आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) टीम ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की सफाई का काम करने वाले इनामी शाहिर तस्करी को उसकी पत्नी और बेटे सहित गिरफ्तार किया है। जिस के चलते इन पर पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं की ओर से आरोपित पर बीस हजार का इनाम रखा हुआ था। एटीएस की टीम ने दो माह तक इन पर नजर रखी जिस के बाद इनकी गिरफ्तारी की । एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि एटीएम टीम ने सीकर जिले से वर्ष 2024 में करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा के तस्करी के मामले में फरार शेखावाट कॉलोनी चूरू निवासी आरिफ हुसैन,उसकी पत्नी शहनाज बानो सहित बेटे जाबिद को एटीएस की टीम ने झुंझुनू जिले के बिसाऊ पुलिस थाना के पास से पकड़ा है। गिरफ्तार इनामी तस्करी

आरिफ हुसैन अपने बेटे जाबिद के नाम से रजिस्टर्ड ट्रक (कंटेनर) से मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी में लिप्त होने पर फरार चल रहा था। आरिफ हुसैन कम पछा लिखा होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से अपनी पत्नी शहनाज बानो के नाम से इनेवा गाडी व बेटे जाबिद के नाम से ट्रक (कंटेनर) खरीदे। मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरिफ हुसैन की पत्नी शहनाज बानो व बेटा जाबिद भी फरार चल रहे थे। इनामी आरिफ हुसैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीकर में किराए का मकान लेकर मजदूरी करने की जानकारी पुलिस टीम को मिली। पिछले दो महीने से एटीएस की टीम सीकर में आरिफ के किराए के घर की पहचान करने के लिए जुटी हुई थी।

टैंक्स चोरी पर ट्रान्सपोर्टर्स के 6 गोदाम सील, 17 वाहन जब्त

जयपुर । राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा की 9 टीमों को गोपनीय रूप से राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर तैनात किया गया। जहाँ से टेकिनकल सर्विलांस के द्वारा बिना ई वे बिल और बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहनित करने वाले 17 वाहनो को जब्त किया गया है। गत सोमवार को जयपुर के 6 प्रमुख ट्रान्सपोर्ट कंपनियों के गोदामों में एक साथ कार्यवाही कर बड़ी कर चोरी उजागर की है। गिल संघु ट्रान्सपोर्ट, जडिया ट्रान्सपोर्ट, क्रियाशक्ति, सुनील ट्रान्सपोर्ट और पीसीएम कार्गो के ये गोदाम जयपुर के वी.के.आई.एरिया तथा ट्रान्सपोर्ट नगर में स्थित है। इन गोदामों से भारी मात्र में रेडीमेड, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रिक आईएम आदि के 1 हजार 960 नमू जम्ब किए हैं। जिनका आर्थिक आकलन किए जाने पर इन्का बाज़ार मूल्य करोड़ों रूपये पाया गया है। यह माल राज्य के बाहर से बिना कर चुकाए राज्य में लाया जा रहा था।

राजेश्वर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया

जयपुर (कासं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं पूर्व राजस्व मण्डल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। सिंह के राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचने पर आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोटिया एवं अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया ।

इस अवसर पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों एवम विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में पूर्णतया वैधानिकता,निष्पक्षता, तटस्थता,तुटिहीनता एवं पारदर्शिता के आधार पर संचर कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी आयोग की मंशा के अनुरूप पूर्ण निष्पक्षता व तटस्थता का परिचय देंगे तथा वैधानिक प्रवधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि राजेश्वर सिंह को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौर एवं जयपुर तथा संभागीय आयुक्त, उदयपुर, भरतपुर व जयपुर के रूप में चुनाव कार्य के प्रबन्धन व पर्यवेक्षण का विस्तृत एवं व्यापक अनुभव है । इसके अलावा वे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण



राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा महा निदेशक,इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के रूप में पंचायती राज प्रशासन एवं प्रशिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं।

परकोटे में दो जर्जर भवन ध्वस्त, दो बिल्डिंग सीज

सुभाष चौक में पुनः जर्जर इमारत गिरने के बाद हैरिटेज निगम की सख्ती

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। सुभाष चौक इलाके में पुनः जर्जर इमारत गिरने के बाद हैरिटेज निगम प्रशासन हरकत में आया है। शुक्रवार को किशनपोल जोन ने परकोटे में दो भवनों के जर्जर हिस्से को ध्वस्त कर दिया, वहीं दो अन्य भवन को खाली करवाकर सीज किया है।

किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने बताया कि जोन कार्यालय की ओर से जर्जर भवनों के निरीक्षण के लिए बनी कमेटी की 14 जर्जर भवनों की रिपोर्ट रैफर की गई थी, जिनमें 7 को पिछले सप्ताह ध्वस्त किया था, शुक्रवार को दो और भवन के जर्जर हिस्से को इंजीनियरिंग विंग की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सतर्कता शाखा की टीम भी मौजूद रहे। लोहा चंडी नाटाणी के रास्ते में एक अन्य जर्जर भवन के नीचे संचालित गोदामों को अस्थायी रूप से सीज गोदाम संचालक को मरम्मत कराने के लिए पाबंद किया है।

वहीं, हवामहल आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने आमेर इलाके में 11 जर्जर भवन का निरीक्षण किया और संचालित खतरे को देखते हुए मकान में रहने वाले लोगों को तुरंत मकान खाली कर



हैरिटेज नगर निगम के किशनपोल जोन की टीम ने इलाके में जर्जर इमारतों को शुक्रवार को ध्वस्त किया।

मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिए। वहीं जर्जर भवन को सीज किया। इस दौरान जोन उपायुक्त ने भवन मालिक से शपथ पत्र लेकर भवन के जर्जर

हिस्से को तुरंत ध्वस्त करने या मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा हैरिटेज निगम की सतर्कता विंग ने बीते दो दिनों में

■ सतर्कता विंग ने चारदीवारी के बरामदों और सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाकर 21 टुक सामान जब्त किया

परकोटे में आम रास्ते और बरामदों से अवैध अतिक्रमण हटाकर 21 टुक सामान जब्त किया है। साथ ही 18 हजार रुपए का चालान भी काटा गया। सतर्कता उपायुक्त पुर्णेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परकोटे में अस्थायी अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ऐसे में सतर्कता शाखा को निर्देश देकर सड़क और बरामदे पर किए जा रहे अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिसमें पुलिस निरीक्षक श्रीमोहन मीणा ने नेतृत्व में विशेष टीम गठन पर राजस्व निरीक्षक जगदीश सरघना ने अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।

इस दौरान गलियों में भी अतिक्रमण कर रहे थड़ी ठेलो को जब्त किया गया। दो दिन में कुल 21 टुक सामान जब्त किया है, साथ ही 13 हजार रुपए परिवहन शुल्क लिया।

कैबिनेट ने स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, मैडिकल कॉलेज फीस व पारितोषिक पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए

जयपुर, 19 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में खेलों को प्रोत्साहित करने, एनआरआई मेडिकल छात्रों के लिए फीस सुधार, दिवंगत कर्मिकों के आश्रितों की पेंशन प्रणाली में सुधार, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और सेवा नियमों में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

राज्य में खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए कैबिनेट ने “महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025”

मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में युवाओं, ऊर्जा व पर्यटन विभाग पर ध्यान दिया गया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

और परफॉर्मैस एनालिटिक्स में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा। यह संस्थान हाई परफॉर्मैस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा।

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन किया गया है। अब एनआरआई कोटा की फीस मैनेजमेंट कोटा की फीस का 2.5 गुना होगी, जो औसतन 23.93 लाख प्रति वर्ष तक की गई है।

कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा

(पेंशन) नियम-1996 में संशोधन करते हुए दिवंगत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता को भी अब 50 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया है। साथ ही, अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी।

बैठक में 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमत पर भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संशोधन को मंजूरी दी है।

चुनाव आयोग के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा जेन जैड को लोकतंत्र के रक्षक कहने की कोशिश को नेपाल, बांग्लादेश और कुछ साल पहले श्रीलंका जैसे देशों में हुए युवा आंदोलनों से जोड़ने की कोशिश बताया, जहाँ बड़े विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकारों में बदलाव हुए थे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी यह सब इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता उन्हें या उनकी पार्टी को वोट नहीं देती। प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं देती। इसलिए वे मोदी जी के 2014 के चुनाव को नकली बता रहे हैं। वे 2019 के चुनाव को फर्जी बता रहे हैं। वे 2024 के चुनाव को भी फर्जी बता रहे हैं। सभी चुनावों को वोटों की धांधली से जीता हुआ बता रहे हैं। राहुल गांधी, कृपया भारत के मतदाताओं की लोकतांत्रिक पसंद का अपमान करना बंद कीजिए।”

बिहार की राजधानी पटना में बोलते हुए, प्रसाद ने कहा कि गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी गड़बड़ी का आरोप

लगाया था, जिसमें उनकी पार्टी कांग्रेस को जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि उस समय पूरी सरकारी मशीनरी कांग्रेस के अधीन थी, फिर भी वे दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। प्रसाद ने यह भी कहा कि उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं थे, फिर भी राहुल गांधी उन्हें कथित “वोट चोरी” के लिए निशाना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने जिस चुनाव की बात की है, वह 2023 का कर्नाटक चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उस समय, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस, प्रशासन सभी उसके अधीन थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अब इतना हो-हल्ला क्यों? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखाई, वे तो इस साल आए हैं, तो 2023 के चुनाव से उनका क्या लेना-देना? झूठ बोलना, बिना प्रमाण आरोप लगाना और देश के सामने गलत तस्वीर पेश करना राहुल गांधी की आदत बन गई है।” प्रसाद ने गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया।

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी को क्या

हो गया है? वे आखिर कितने झूठ बोलेंगे? वे कितनी बातें तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे? मैं इससे भी सख्त शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी, यह मेरी संस्कृति नहीं है, न ही मेरी पार्टी की। लेकिन आप देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, 2023 से कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, और सीआईडी उसके अधीन है, तो न वे होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, वे झूठे आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और यह उनकी प्रकृति बन चुकी है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिरा दिया है।” ज्ञातव्य है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वोटरों के नाम हटाये जाने का विवरण माँगा है।

भाजपा सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पार्टी और एनडीए नेताओं को राहुल गांधी पर आक्रामक हमला करने का निर्देश देने के बाद, उन पर यह तीव्र हमला शुरू हुआ है, क्योंकि “वोट चोरी” के खिलाफ राहुल गांधी का अभियान बिहार सहित देश के कई हिस्सों में लोगों के बीच पकड़ बना रहा है।

लोकसभाध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि वे एफ आई आर दर्ज करने की प्रक्रिया को रोकते हैं एक बार फिर से प्रभावित करते हैं या रोका गया, तो यह कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। यह जग जाहिर है कि राजीव दत्ता और ओम बिडला कोटा के दिनों से बेहद करीबी रहे हैं, और अब यह दोस्ती सबके सामने आ गई है, क्योंकि बिडला खुद दत्ता को एफ आई आर से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार और दत्ता दोनों को कोई राहत नहीं मिली है। अब यह स्थिति साफ इशारा करती है कि राजीव दत्ता के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि यह एक संवेदनशील पद है। इसके साथ ही, जयपुर पुलिस एफ आई आर दर्ज करने से बचती आ रही है, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि दत्ता ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक पर एफ आई आर दर्ज न करने के लिए दबाव डाला है। इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर, ओम बिडला का सािलिसिटर जनरल से मिलने जाना खुद ही हालात साफ कर देता है।

ट्रंप के टैरिफ के “श्राप” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्तित्व बचाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक मजबूत बढ़त है। उसके मुनाफे सुरक्षित रहते हैं, निर्यात मात्रा स्थिर रहती है और अमेरिकी साझेदार आश्वस्त रहते हैं। इसके विपरीत, छोटे भारतीय निर्यातकों के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैमाना या सीमा-पार नेटवर्क नहीं है, इसलिए ये कमजोर व असुरक्षित बने रहते हैं। नतीजा है, संगठित आभूषण दिग्गजों और पारंपरिक खिलाड़ियों के बीच खाई बढ़ रही है।

गोलिडयम का यह कदम एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, दुनिया भर के निर्यातक उद्योग की दीवारों से टकराने के बजाय उनके इर्द-गिर्द घूमना सीख रहे हैं। चीन की कंपनियों ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान अपनी असंबली लाइनों का मार्ग वियतनाम और मलेशिया की तरफ मोड़ दिया है। मैक्सिकन ऑटो सप्लायर लंबे समय से लागत और टैरिफ के असर को बेहतर तरीके से

- स्थापित ज्वैलर्स, जिनके पास अमेरिका में सोना खरीदने का सामर्थ्य व संगठन है, वो ही यह सारी कसरत कर सकते हैं। पर, छोटे-छोटे देशों के उभरते ज्वैलर्स के लिए यह सब करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। अतः वे “इनोवेटिव” व सामर्थ्य पूर्ण भारतीय ज्वैलर्स की तुलना में टिक नहीं पायेंगे।
- अतः भारतीय ज्वलैर्स ने न केवल अपने माल को भारी टैरिफ (50 प्रतिशत) की मार से बचा लिया, बल्कि एक तरह से अमेरिका के ज्वैलरी के मार्केट में छोटे-मोटे सप्लायर्स की पहुँच को खत्म कर दिया व अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया।

निर्यात करने के लिए उत्तरी अमेरिकी व्यापार ढाँचे का लाभ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि वियतनाम के गारमैंट एक्सपोर्टर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत ड्यूटी फ्री प्रावधानों का लाभ उठाकर सफल हो रहे हैं। इन सभी उदाहरणों को जो बात जोड़ती है, वह है सोच में बदलाव। टैरिफ, जो कभी संरक्षणवाद के भीथरे औजार माने जाते

थे, अब सप्टाई चैन डिजाइन में इनोवेशन (नवाचार) लाने वाले बन रहे हैं। वैश्विक पहुँच और कुशल रणनीतियों वाली कंपनियाँ अक्सर जोखिम को कम करने के लिए कानूनी रास्ते खोज लेती हैं, जबकि छोटे खिलाड़ी गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। भारत के आभूषण उद्योग के लिए सबक स्पष्ट है। अमेरिका इसका

सबसे बड़ा बाजार है और संरक्षणवादी कदम बार-बार उठते रहेंगे। व्यावसायिक मॉडलों को नए सिरे से ढालने की क्षमता, चाहे वह अमेरिका से प्राप्त सोने के माध्यम से हो, विदेशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से हो, या डिजाइन और ब्रांडिंग की सीढ़ी पर आगे बढ़ने के माध्यम से हो, यह तय करेगी कि कौन फलता-फूलता है और कौन पीछे छूट जाएगा। 1986 में स्थापित गोलिडयम ने दिखाया है कि वह कैसे अनुकूलन कर सकता है और जीत सकता है। 50 प्रतिशत के दंडात्मक टैरिफ को एक प्रबंधनीय लागत (मैनेजेबल कॉस्ट) में बदलकर, इसने दुनिया के सबसे आकर्षक आभूषण बाजार में अपनी चमक बरकरार रखी है। इससे भी बढ़कर, इसने व्यापक रूप से भारतीय निर्यातकों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की है, व्यापार अनिश्चितता के नए युग में असली बात यह नहीं है कि आप क्या बेचते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे बाजार तक पहुँचाने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाते हैं।

‘आईबी के आग्रह पर मैं आतंकियों ...

- मलिक ने कहा, 2000 में देश में वाजपेयी सरकार के समय में सीबीआई के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल जेल में मुझ से मिलने आए थे, उन्होंने मुझे आईबी डायरेक्टर श्यामल दत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा से मिलवाया। वे चाहते थे कि मैं उनके रमजान सीज़फायर को सपोर्ट करूँ।
- मलिक ने कहा, नब्बे के दशक के बाद से लगातार 6 सरकारों (वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक) ने कश्मीर मसले के समाधान प्रक्रिया में मुझे शामिल किया था।
- यासीन मलिक ने यह हलफनामा एनआईए के आरोप पत्र के जवाब में दिया है। एनआईए ने आतंकवाद में भूमिका के लिए मलिक को मृत्युदंड देने की माँग की है।

मुझसे नई दिल्ली में मुलाकात की और मेरी रिहाई की सूचना दी। उन्होंने मेरी मुलाकात आईबी निदेशक श्यामल दत्ता और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा से करवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर वार्ता को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि मैं रमजान संघर्ष विराम का समर्थन करूँ।” मलिक ने दावा किया कि उन्होंने शांति प्रक्रिया में समर्थन पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वामपंथी नेताओं (जो उस समय विपक्ष में थे) से भी मुलाकात की थी। मलिक ने कहा, 2002 में मैंने पूरे जम्मू-कश्मीर में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसका मकसद कश्मीर में अहिंसक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना और कश्मीरी

नेतृत्व को संवाद प्रक्रिया में शामिल करना था। यह बेहद कठिन कार्य था, और मुझे हर गाँव, स्कूल और कॉलेज जाकर 1.5 मिलियन (15 लाख) हस्ताक्षर एकत्र करने में ढाई साल लगे। सन् 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 2006 में पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वे कश्मीर मसला हल करना चाहते हैं। मुलाकात के बाद मलिक अमेरिका गए और वहां स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की। हालाँकि, इसके बाद तत्कालीन पीएम को आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखा। मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें केवल देश में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर

कश्मीर मुद्दे पर बोलने के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा, मुझे केवल घरेलू मंच ही नहीं, बल्कि बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया। मलिक ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार में शामिल होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। “ऐसे निराधार दावे हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन मेरे द्वारा किए गए नरसंहार और सामूहिक हिंसा के कारण हुआ। अगर यह साबित हो जाए, तो मैं बिना किसी मुकदमे के खुद को फांसी पर लटकवा लूंगा और इतिहास में अपने नाम को एक अभिशाप के रूप में दर्ज करवाऊंगा।” दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में निर्धारित है।

TRUE VALUE

60 लाख यात्राएँ, अनगिनत खुशियाँ आपके भरोसे का प्रतीक

CELEBRATING 60Lakh STORIES OF TRUST

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

UDAIPUR: S-140, MADRI INDUSTRIAL AREA, UDAIPUR, NAVNEET MOTORS: 7230016838, 9929140770, 8209069304 | SUKHER, 200 FEET ROAD, SUKHER BYE PASS, KHELGAON ROAD, NEAR BHERAVGARH RESORT, UDAIPUR, TECHNOY MOTORS: 8112266227, 9773346347, 9001237506, 9773346344 | THIKARIA DAHOD ROAD, BANSWARA, NAVNEET MOTORS: 7665887333, 7597349534 | BANSWARA: THIKARIA DAHOD ROAD, BANSWARA, NAVNEET MOTORS: 7665887333, 7597349534.

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। छवियों का इस्तेमाल केवल उदाहरण मात्र है।

TRUE VALUE CERTIFIED

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वैरिड मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायन हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हट्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय :- एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908